भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2506

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र के कार्यशील उद्योग

2506. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यवतमाल-वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के कार्यशील उद्योगों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़े सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या कितनी है;
(घ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में चीनी कारखानों में कुल कितने कामगार कार्यरत हैं;
(ङ) बोधेगांव में मुंगसाजी जय किसान सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड की वर्तमान स्थिति क्या है;
(च) उक्त चीनी कारखाना शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और
(छ) इस कारखाने के कब तक चालू होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल पर आरसीएस महाराष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, यवतमाल और वाशिम जिलों में कार्यशील, गैर-कार्यशील/निष्क्रिय और परिसमापनाधीन कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समितियों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 05.12.2024 के डेटा अनुसार

जिले	कार्यशील		गैर-कार्यशील/निष्क्रिय		परिसमापनाधीन	
	समितियों की संख्या	सदस्य	समितियों की संख्या	सदस्य	समितियों की संख्या	सदस्य
वाशिम	72	1575	1	765	0	0
यवतमाल	158	63465	1	0	6	59
वाशिम और यवतमाल में पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियां	0	0	0	0	0	0

हालांकि, सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहकारी अधिनियम के तहत विनियमित सहकारी समितियों में कामगारों के डेटा का अनुरक्षण नहीं करता है।

(ड) से (छ): नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (NFCSFL) द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, मुंगसाजी जय किसान सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड बोधेगोन SARFAESI अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार परिचालन में नहीं हैं और परिसमापन के अधीन है। उक्त सहकारी चीनी मिल ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (MSC Bank), मुंबई के बकाया 232.48 करोड़ रुपये के अपने बकाया का भुगतान नहीं किया है और परिणामस्वरूप बैंक ने अपनी संपत्ति कुर्क कर ली है और बकाया वसूली की सुविधा को पट्टे पर देने के लिए एक सार्वजनिक निविदा जारी की है। उक्त सहकारी चीनी मिल के परिचालन या अन्यथा की समय सीमा (एमएससी बैंक) द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर करती है।

महाराष्ट्र की चीनी मिलों सहित सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित पहलों की हैं:-

1. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत राहत के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार:

- (i) चीनी सहकारी मिलों को आयकर से राहत: वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में धारा 36 (1) (xvii) को शामिल किया गया था, ताकि चीनी के निर्माण के व्यवसाय में संलग्न सहकारी समिति यानी सहकारी चीनी मिलों (CSMs) द्वारा किए गए व्यय की राशि पर कटौती प्रदान की जा सके। यह उपाय दिनांक 1.4.2016 यानी आकलन वर्ष 2016-17 से लागू हुआ। हालांकि, किसान सदस्यों और परिणामी कर देनदारियों को आय वितरण के रूप में सहकारी चीनी मिलों (CSMs) द्वारा गन्ना मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान के उपचार का मुद्दा उजागर रहा, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या 18 / 2021 दिनांक 25.10.2021 के अनुसार स्पष्ट किया गया था। तदनुसार, उनके द्वारा गन्ना मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान पर CSMs पर परिणामी कर देनदारियों को 1.4.2016 से कम कर दिया गया।
- (ii) सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान: चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा व्यय के रूप में करने का अवसर प्रदान किया गया है। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 155 को भी वित्त अधिनियम, 2023 के तहत एक नई उपधारा (19) सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया गया है। अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (19) के तहत क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन दाखिल करने के तरीके और उक्त धारा के तहत क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इसके निपटान के तरीके को मानकीकृत करने के लिए, CBDT ने दिनांक 27.07.2023 के परिपत्र संख्या 14/2023 के तहत संबंधित सहकारी चीनी मिलों द्वारा आवेदन करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। इससे दशकों से लंबित इस मामले में आयकर के मुद्दों का समाधान हुआ है। इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।

2. भारत सरकार ने सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को मजबूत करने के लिए "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को सहायता अनुदान" नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना में इथेनॉल संयंत्रों/सह-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना और उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीएसएमएस को 10,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। एनसीडीसी ने अब तक 58 सहकारी चीनी मिलों को 8040.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने 05 सितंबर, 2020 को एक संकल्प जारी किया है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी चीनी कारखानों को पट्टे पर देने, साझेदारी करने या सहयोग करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। यह संकल्प पारदर्शिता, सतत संचालन, वित्तीय अनुशासन और किसानों और श्रमिकों जैसे हितधारकों को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। यह संकल्प MSC बैंक को कारखाने को पुनर्जीवित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञता के लिए अवसर प्रदान करते हुए बकाया राशि की वसूली के लिए SARFAESI के तहत कदम उठाने में सक्षम बनाता है।